कलेक्टर ऑफ कस्टमस

बनाम

मैसर्स टेलीविजन एवं कम्पोनेन्टस लि- एवं अन्य

24 फरवरी, 2000

(एस.पी. भारूचा एवं मिसेज रूमा पाल, जे.जे.)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962/सीमा शुल्क मुल्यांकन (आयात शुल्क के मुल्य का निर्धारिण) नियम 1988- धारा 14, 108 और 111/ नियम 3 दो फर्मा से टेप डेस्क मैकेनिज्म्स आयात- डुप्लीकेट चालान और छापों के दौरान बरामद समान संख्या और तिथि जिससे विभिन्न मुल्यों का खुलासा हुआ, वाले और्डर-कम चालान और माल के मुल्य की गलत घोषणा और परिणामी सीमा शुल्क की चोरी का चार्ज- लेन-देन मुल्य-अंतर सीमा शुल्क का अधिरोपण- प्रतिपादित, मान्य।

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947- धारा 3 (2)- आयात नियंत्रण आदेश, 1955- खण्ड 3- टेप डेस्क मैकेनिज्म ओ.जी.एल. सूची से हटा दिया- आयात के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति- छूट का लाभ उठाने के लिए गलत निरूपण पर खोले गए ऋण पत्रों में संशोधन- बिना अनुज्ञप्ति की आवश्यकता के माल का आयात- प्रतिपादित किया गया,

न्याय निर्णायक प्राधिकारी को उल्लंघन का निर्णय करना चाहिए- न्याय निर्णयन का दायरा स्पष्ट किया गया है।

जुर्माना- आयात नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के लिए कलेक्टर द्वारा लगाया गया समग्र जुर्माना और आयोजित माल के मुल्य में गलत घोषणा- प्रतिपादित किया गया, प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति पहलू पर मुद्दे का निर्धारण करने के बाद कलेक्टर द्वारा जुर्माने का पुर्ननिर्धारण करना होगा।

प्रतिवादी-कंपनी ने एक विदेशी फर्म Y से S 250.00 प्रति सेट पर टेप डेस्क मैकेनिज्म (टीडीएम) आयात किया। आयात खेप को राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कम चालान और जांच के लिए आयात नियंत्रण आदेश 1955 के प्रावधानों की उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने पर रोक दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा, एक रिट पर जांच को चुनौती देते हुए प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका में निर्देश दिया गया है डीऔरआई को दो महीने के भीतर जांच पूरी करनी है। डीऔरआई द्वारा प्रतिवादी के कार्यालय और फैक्ट्री परिसरों पर छापे मारे गए और कई दस्तावेज़ों की बरामदगी की गई। प्रबंध निदेशक एवं समाशोधन एजेंट सहित अन्य व्यक्तियों से आयात अधिनियम,1962 की धारा 108 से बयान को एकत्र किया गया था। टीडीएम को डीऔरआई द्वारा जब्त कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा जब्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुरक्षा के विरुद्ध टीडीएम को अस्थायी रूप से मुक्त करने का निर्देश दिया।

डीऔरऔई ने छापे में समान संख्या वाले समान ऑर्डर बरामद किए और तारीखें, दिसंबर 1988 और जनवरी 1989 के महीनों से संबंधित,प्रतिवादी द्वारा किसी अन्य फर्म एम के साथ टीडीएम की आपूर्ति के लिए एस$343.50 प्रति सेट पर रखा गया जैसा कि फर्म वाई के साथ रखा गया है। मार्च 1989 में, एक सार्वजनिक सूचना द्वारा,टीडीएम को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) सूची से हटा दिया गया और आयात और निर्यात नीति के तहत आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता हुई। तथापि,सार्वजनिक नोटिस में बिना लाइसेंस के टीडीएम के आयात की अनुमति दी गई है, जहां-अप्रवर्तनीय ऋण पत्र (एल/सी) सार्वजनिक सूचना की तारीख से पहले खोले गए थे नोटिस बशर्ते कि शिपमेंट सार्वजनिक सूचना की तारीख 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाए. छूट का लाभ उठाने के लिए, राजस्व ने पाया कि प्रतिवादी ने अपने बैंकर द्वारा एल/सी में संशोधन प्राप्त किया, जो मूल रूप से फर्म एम के पक्ष में जनवरी 1989 में खोला गया था। गलतबयानी है पर कि फर्म वाई, फर्म एम का एजेंट था। राजस्व ने पाया गया कि फर्म वाई, फर्म एम से स्वतंत्र है और जनवरी 1989 में फर्म वाई को दिया गया ऑर्डर मनगढ़ंत है। राजस्व ने यह भी पाया कि मार्च 1989 के बाद एक नए एल/सी के साथ फर्म वाई को ऑर्डर दिए गए, जिसे आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता थी, जो प्रतिवादियों के पास नहीं था। राजस्व ने आगे पाया कि टीडीएम के घोषित

मूल्य में एस 343.50 से एस 250.00 गिरावट टीडीएम के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

सीमा शुल्क कलेक्टर ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि प्रतिवादी S 250.00 के बजाय S 343.45 प्रति सेट पर टीडीएम की गणना और आयात नियंत्रण आदेश का पालन के उल्लंघन के संबंध में शुल्क के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है - कलेक्टर ने एक आदेश द्वारा यह माना कि प्रतिवादी ने 32,03,594 रुपये की सीमा शुल्क की चोरी की।और पूरी खेप चोरी के आधार पर आयात लाइसेंस के बिना टीडीएम का अवैध आयात के कारण अधिनियम के तहत जब्त करने के लिए उत्तरदायी थी, जो कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम और आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है- चूंकि माल उच्च न्यायालय के निर्देशों पर मुक्त किया गया था, कलेक्टर ने प्रतिवादी-कंपनी को चोरी की अंतर सीमा शुल्क के भुगतान करने का आदेश दिया और 40 लाख रुपये का जुर्माना, माल का प्रतिदेय मूल्य और प्रत्येक उत्तरदाताओं-प्रबंध निदेशक और निदेशक द्वारा रु. 5 लाख का अतिरिक्त जुर्माना। प्रतिवादी द्वारा अपील में, ट्रिब्यूनल ने विभेदक शुल्क और जुर्माने को रद्द कर दिया। ट्रिब्यूनल ने आगे कलेक्टर को उच्च न्यायालय के निर्देशों और राजस्व के तर्क के

अनुसार,निर्देश देते हुए लाइसेंसिंग पहलू का पुनः निर्णय हेतु वापस भेज दिया।

इस न्यायालय में अपील में, राजस्व ने तर्क दिया कि प्रतिवादी टीडीएम को कम चालान करके आयात किया गया,कि मूल्य में गलत घोषणा के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क की चोरी हुई, और टीडीएम के आयात से आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात नियंत्रण आदेश 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। क्याेकि आयात बिना लाइसेंस के किया गया था आवश्यकता अनुसार।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि मूल्य में गलत घोषणा और कम चालान नहीं की गई थी और फर्म वाई और फर्म एम द्वारा आपूर्ति किए गए टीडीएम अलग-अलग मॉडल हैं।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिपादित किया गया:

प्रतिपादित किया गया: **1.1.** कलेक्टर का निष्कर्ष कि फर्म वाई से आयात किया गया टीडीएम को S 250.00 के बजाय S 343.45 का मूल्य होना उचित था, तथ्य में स्वीकार्य है और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का पालन कर रहा था। [1146-सी]

1.2. प्रतिवादियों का यह तर्क है कि फर्म वाई और फर्म एम द्वारा आपूर्ति की गई टीडीएम अलग-अलग मॉडल हैं, कभी भी स्थापित नहीं किया गया था और सबूत के विपरीत था। प्रतिवादी-कंपनी ने फर्म एम से टीडीएम के 500 सेट प्रति सेट एस$260 पर और टीडी एमएस के 3000 सेट एस$250 पर आयात करने के लिए एल/सी का उपयोग किया। फर्म वास्तव में एल/सी के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था उस सामान की प्रकृति जिसके लिए प्रारंभ में एल/सी खोला गया था। दूसरे शब्दों में, एस 343.45 के टीडीएम का प्रकार और दर वही रही। एल/सी का लाभ उठाते हुए, संबंधित पक्षों को ऐसा करने के लिए सहमत होना चाहिए। फर्म एम पर दिए गए मूल आदेश की पूर्ति जहां दर का उल्लेख किया गया है S 343.45 प्रति सेंट था। दूसरा, वाई के चालान से जिसे सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ दाखिल किया गया था, ने भी समान मॉडल के टीडीएम का वर्णन किया। प्रतिवादी-प्रबंध निदेशक ने अधिनियम की धारा 108 के तहत अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि वास्तव में फर्म वाई को 5.1.1989 को कोई आदेश नहीं दिया गया था और एकमात्र वास्तविक ऑर्डर वह था जो फर्म एम को दिया गया था। चूंकि फर्म वाई की टीडीएम के 3000 सेट की आपूर्ति फर्म एम के आदेश के अनुसार थी, इसे यह माना जाएगा कि उसने उसी सामान की आपूर्ति S 343.45 प्रति सेट की दर से की है। तीसरा, जो टीडीएम फर्म वाई द्वारा आपूर्ति किए गए थे वे वही थे जिसके लिए फर्म एम को आदेश दिया गया

था और यह अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज बयानों द्वारा समर्थित है। क्लियरिंग एजेंट ने धारा 108 के तहत अपने बयान में कहा कि प्रतिवादी द्वारा दिखाई गई टीडीएम की कीमत असामान्य रूप से कम थी। कलेक्टर ने सही निर्णय लिया कि फर्म वाई द्वारा "ऐसे या इसके जैसे" सामान के लिए आपूर्ति किए गए टीडीएम का मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14(1) के अर्थ के तहत फर्म एम को आदेश दिया गया था। कलेक्टर का निष्कर्ष भी अधिनियम की धारा 14(1ए). इसके तहत उचित है। (1149-बी-एच; 1150-जी; 1151-जी]

सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता बनाम संजय चांदीराम, [1995] 4 एससी 222 और नरेश जे. सुखवानी बनाम भारत संघ,(1996) 83 ईएलटी 258 एससी, पर भरोसा किया गया।

1.3. जो और्डर फर्म एम को एसएस 343.45 प्रति सेट पर दिया गया था उन टीडीएम की आपूर्ति फर्म वाई द्वारा की गई थी। माल के लिए 'देय मूल्य' प्रति सेट S 343.45 पर रहा जो कि सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का निर्धारण) नियम 1988 के नियम 3 के अर्थ के तहत लेन-देन मूल्य है। कलेक्टर का निष्कर्ष कि टीडीएम की इकाई कीमत एस$343.45 है और विभेदक शुल्क के भुगतान के संबंध में आदेश को बरकरार रखा गया है। (1152-डी-एच]

2. आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के अनुसार बिना लाइसेंस के टीडीएम के आयात के संबंध में निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को यह निर्णय लेना चाहिए कि (i) क्या कानून के अनुसार, पूर्व में आयातित वस्तुआेंं के संबंध में बाद में कोई तैयार की गई अनुज्ञप्ति कानून में स्वीकार्य है; (ii) यदि हां, तो क्या लाइसेंस हैं वास्तव में इसमें आयातित वस्तुएं शामिल हैं और अन्यथा वैध हैं। (1153-एफ)

3. कलेक्टर द्वारा लगाया गया जुर्माना एक समग्र जुर्माना था, जो आयात नियंत्रण आदेश के उल्लंघन और मूल्य की गलत घोषणा और सीमा शुल्क की चोरी दोनों के कारण लगाया गया था। पाए गए उल्लंघनों के बीच जुर्माने की मात्रा का बंटवारा करें यह संभव नहीं है। यद्यपि गलत घोषित करने और चोरी के मामले पर कलेक्टर के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए, जुर्माने की मात्रा का प्रश्न कलेक्टर द्वारा लाईसेसिंग के मुद्दे का निर्धारण करने के बाद फिर से निर्धारित किया जाएगा। ट्रिब्यूनल द्वारा एेसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया कि लगाया गया जुर्माना अनुचित था. मामले की परिस्थितियों के अनुसार जुर्माने की राशि उचित था. (1153-एच; 1154-ए-बी]

4. जहां तक यह गलत घोषणा और चोरी के निष्कर्ष से संबंधित है, ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द कर दिया गया है। कलेक्टर का अंतर शुल्क के भुगतान के आदेश की पुष्टि की जाती है। आयात नियंत्रण आदेश का

उल्लंघन के प्रश्न पर, निर्णायक प्राधिकारी मामले को तय करेगा। उसके फैसले के आधार पर इसके बाद जुर्माने की राशि तय होगी। निष्कर्षों के आलोक में कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। [1154-सी-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नं. 9026-9028/1996

दिनांक 24-03-95 को केन्द्रीय सीमा शुल्क और सोना (नियंत्रण(अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली, पो.ओ . नं. 244-246 ऑफ 1995 इन ए. नंबर C/725/92-A, C/726· 727/92-A.

एच.एन. साल्वे, सालिसिटर जनरल, के.एन. भट, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, वसीम ए कादरी, वाई.के. वर्मा, ए. सुबाराव, निखिल सखरडण्डे, पी. परमेंश्वरन एवं एस.के. अग्निहोत्री- अपीलीर्थी की तरफ से।

ए.बी. रोहतगी, जोसफ वेलापल्लई, मिस. अपर्णा रोहतगी, के.बी. रोहतगी, महेश कसाणा, महेश रोहतगी एवं एस.वाई. देशपाण्डे- प्रतिवादी की और से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया रूमा पाल, जे. के द्वारा सुनाया गया।

(1) इन अपीलों में मुद्दे प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा टेप डेक मैकेनिज्म (टीडीएम) के आयात से उत्पन्न हुए हैं। अपीलार्थी के अनुसार न केवल टीडीएम को बहुत कम मूल्य पर आयात किया गया था,जिसके

परिणामस्वरूप उन्हें उचित सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ा पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात नियंत्रण आदेश 1955 के प्रावधानों के विपरीत था।

(2) टीडीएम को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एस $ 250.00 प्रति सेट पर यमातो इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड से (इसके बाद संदर्भित)। 'यमाटोस) से आयात किया गया था । खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई कि आयातित टीडीएम धोखाधड़ी से कम चालान किया गया और आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के प्रावधान का उल्लंघन किया गया था, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा खेप को कांडला बंदरगाह पर रोक लिया गया था। जांच डीआरआई द्वारा शुरू किए गए थे। प्रतिवादी संख्या 1 ने जांच को अनुच्छेद 226 के तहत गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। रिट याचिका को डीआरआई की जांच पूरी करने और दो माह में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश के साथ निस्तारित किया गया।

(3) डीआरआई द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के कार्यालय और फैक्ट्री परिसरों पर छापे मारे गए और कई दस्तावेज बरामद किए गए। प्रबंध निदेशक, निदेशक और सहायक प्रबंधक के साथ प्रतिवादी नंबर 1 के समाशोधन एजेंट के धारा 108 सीमा शुल्क' अधिनियम, 1962 ('अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत बयान दर्ज किए गए थे।

(4) टीडीएम जब्त कर लिए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने टीडीएम की जब्ती को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में दूसरा रिट आवेदन दायर किया।. हाईकोर्ट ने सुरक्षा के विरुद्ध टीडीएम के औपबंधिक रिहाई का निर्देश दिया। माल तदनुसार मुक्त किया गया था लेकिन जांच जारी रही।

(5) बरामद दस्तावेजों और धारा 108 के तहत बयानों के आधार पर प्रतिवादि को 15 जून, 1990 को विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया कि प्रतिवादी नंबर 1 एस 250.00 के स्थान पर एस 343.45 प्रति सेट की दर से गणना की गई टीडीएम के अंतर शुल्क भुगतान के लिए उत्तरदायी है व आयात नियंत्रण आदेश के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। प्रतिवादी नंबर । ने नोटिस का उत्तर दिया। कलेक्टर ने प्रतिवादियों को सुनने का मौका दिया।

(6) कलेक्टर ने साक्ष्यों पर विचार करने के बाद पाया कि यहाँ मूल्य की जानबूझकर गलत घोषणा, दस्तावेजों में हेराफेरी, पूर्ण सीमा शुल्क के भुगतान से बचने के लिए प्रयास और प्रतिवादी संख्या 1 और उसके निदेशकों द्वारा आयात नियत्रंण विनियम को दरकिनार करने का प्रयास था। कलेक्टर के अनुसार, प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा आयातित टीडीएम एस$250.00 प्रति सेट पर सिंगापुर डॉलर 343.45 प्रति सेट का मूल्य था और यह कि प्रतिवादी नंबर । को टीडीएम का मूल्य घोषित करना चाहिए

था रुपये पर घोषित मूल्य 64,30,847 रुपये के मुकाबले 88,34,698 रुपये है। इसलिए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी नंबर 1 ने रुपये 32,03,594.00 की सीमा तक शुल्क से बचने की मांग की थी और वह पूरी खेप अधिनियम की धारा 111 (एम) के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी थी। कलेक्टर ने भी यह बात कही टीडीएम को एक आयात अनुज्ञप्ति की आवश्यकता थी और चूंकि आयात अनुज्ञप्ति पेश नहीं की गई,माल धारा 111(डी) सीमा शुल्क अधिनियम, सपठित धारा 3(2) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा खण्ड 3, आयात नियंत्रण आदेश, 1955।

(7) उसके निष्कर्षों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माल उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पहले ही रिहा कर दिया गया है, प्रतिवादी नंबर 1को 32,03,594.00 रुपये का अंतर शुल्क का भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया और अधिनियम की धारा 112(ए) के तहत प्रतिवादी नंबर 1 पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया (माल के प्रतिदेय मूल्य के रूप में) और 5 लाख रु प्रतिवादी नंबर 1 के प्रबंध निदेशक और निदेशक प्रत्येक पर।

(8) प्रतिवादी नंबर 1 और उसके निदेशकों ने ट्रिब्यूनल के दो सदस्यों के समक्ष अपील दायर की।

(9) अपील के लंबित रहने के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर एक रिट आवेदन पर 26 तारीख को एक आदेश पारित किया।जून, 1992 निम्नलिखित प्रभाव से:

"नोटिस। श्री बी.बी. नाइक, विद्वान गिनती:एल, नोटिस की सेवा माफ करते हैं।

हमने श्री एस.आई. नानावटी को सुना, याचिकाकर्ताओं का पक्ष सीखा और श्री एच.एम. मेहता, केंद्र सरकार के वरिष्ठ स्थायी सलाहकार-सेल, प्रतिवादियों के लिए।

हमें सूचित किया गया है कि 26 फरवरी, 1992 के निर्णय आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ताओं ने पहले ही प्राथमिकता दे दी है एक अपील। एकमात्र शिकायत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 नहीं है याचिकाकर्ताओं को आयात लाइसेंस प्रस्तुत करने की अनुमति देना। उसका प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित करके शिकायत को सुधारा जा सकता है आज से दो सप्ताह के भीतर आयात लाइसेंस स्वीकार करें और प्रतिवादी नंबर 2 कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएगा।इस याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के तहत किया जाता है। नोटिस गायब है- आरोपित. कोई लागत नहीं।"

(10) जहां तक ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील की बात है, एक पर कलेक्टर के आदेश को बरकरार रखा जाए या नहीं, इस पर दोनों सदस्यों के बीच मतभेद होने पर मामला तीसरे के पास भेजा गया। सदस्य। तीसरे सदस्य ने इस विचार से सहमति व्यक्त की कि के आदेश जहां तक कलेक्टर ने सिंगापुर डॉलर में टीडी एमएस के मूल्य का आकलन किया 343.45 गलत था. परिणामस्वरूप, विभेदक शुल्क लगाना निर्धारित किया गया एक तरफ. आयात नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के सवाल पर ट्रिब्यूनल ने उच्च न्यायालय के आदेश और विभागीय प्रतिनिधि की इस रियायत के आधार पर कार्रवाई की कि यह मुद्दा "मूल" है प्राधिकरण" को इस पर गौर करना होगा और निर्णय लेना होगा और मामले को वापस भेजना होगा पार्टियों को कोई भी प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ कलेक्टर के पास वापस भेजा जाएगा इस संबंध में निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष ताजा साक्ष्य। दृष्टि मे इस आदेश में कलेक्टर द्वारा प्रतिवादियों पर लगाया गया जुर्माना भी रद्द कर दिया गया।

(11) इसके बाद इन अपीलों को प्राथमिकता दी गई। कोई ठहराव नहीं रहा मान लिया गया, ट्रिब्यूनल के आदेश पर फिर से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया लाइसेंसिंग पहलू लिया गया था. 27 तारीख को सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा सितंबर, 1995। आयुक्त के समक्ष, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अतिरिक्त लाइसेंस प्रस्तुत किए गए थे। यह नोट किया गया था कि

चूंकि यह पहले से ही था कलेक्टर ने पाया कि लाइसेंस में प्रश्नगत सामान शामिल है, और कि इस मुद्दे को ट्रिब्यूनल, लाइसेंस के समक्ष आगे नहीं बढ़ाया गया था स्वीकार किया जाना चाहिए. आदेश, कुछ हद तक अस्पष्ट रूप से, के साथ समाप्त होता है

वाक्य:

"हालांकि, यदि विभाग अब लाइसेंस स्वीकार नहीं करने का निर्णय लेता है- सीईएस, आईटीसी के नजरिए से मामले की खूबियों पर बहस करने के लिए पार्टी को एक और सुनवाई का मौका दिया जा सकता है।

(12) अपीलकर्ता द्वारा हमारे सामने उठाया गया पहला प्रश्न किससे संबंधित है मूल्य की गलत घोषणा और सीमा शुल्क की चोरी का पता लगाना। हमारी राय में, कलेक्टर का निष्कर्ष है कि टीडीएम का आयात किया गया था यमातो का मूल्य S$250.cn के बजाय S$343.45 होना उचित था वास्तव में और संबंधित वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए था विषय। जहां तक तथ्यों पर निष्कर्ष का सवाल है, प्रासंगिक और स्वीकृत तथ्य हैं

कालानुक्रमिक रूप से निर्धारित करना आवश्यक है।

(13) प्रतिवादी नंबर 1 ने आपूर्ति के लिए मिस मोहन एलएमपीईएक्स पर जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर 1988 में कई

ऑर्डर दिए थे। टीडी सुश्री। किसी भी आदेश में टीडीएम के मॉडल या बनावट का उल्लेख नहीं किया गया। पिछली प्रत्येक खेप प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्राप्त की गई थी मिस मोहन एलएमपीईएक्स @ एसएस 343.45 प्रति सेट से।

(14) जहां तक प्रश्नगत खेप का सवाल है, ओ.और.आई एक ही नंबर वाले दो समान प्रोफार्मा चालान बरामद किए गए टीडीएम के 3 जी(एल() सेट की आपूर्ति के लिए दिनांक 29.12.98। दोनों 'डब्ल्यू'जे' के चालान थे मोहन एलएमपीईएक्स लेकिन एक में उद्धृत मूल्य एस 343.45 प्रति सेट था अन्य S 250.C:। प्रति सेट के लिए। उत्तरदाता स्पष्ट नहीं कर पाये हैं चालान का यह दोहराव.

(15) प्रतिवादी नंबर 1 ने फिर मेसर्स मोहन पर एक आदेश दिया एलएमपीसीएक्स की आपूर्ति के लिए आदेश संख्या टीसी-89-004 दिनांक 5 जनवरी 1989 है। एसएस 343.45 प्रति सेट पर टीडीएम के 30 सीओ सेट। ओऔरआई ने एक समान बरामद किया प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा समान संख्या और तारीख वाला आदेश दिया गया

यमातो लेकिन एस 250.00 प्रति सेट। प्रतिवादी नंबर एल के निदेशक धारा 108 के तहत अपने बयान में स्वीकार किया कि कोई आदेश नहीं दिया गया था 5.1.89 को यमातो और यह एक मनगढ़ंत दस्तावेज़ था।

(16) प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साख पत्र स्थापित किया गया था बैंक ऑफ इंडिया ने "इलेक्ट्रॉनिक्स" की आपूर्ति के लिए मिस मोहन इम्पेक्स के पक्ष में समझौता किया वीसीऔर के लिए एच घटक, अर्थात। आदेश संख्या टीसी के अनुसार टेप दिसंबर तंत्र- 80-004 दिनांक 5 जनवरी 1989"।

(17) इसमें कोई विवाद नहीं है कि 21 मार्च 1989 तक, टीडीएम को कवर किया गया था की आयात और निर्यात नीति के तहत ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) द्वारा अप्रैल 1988 से मार्च 1991। सार्वजनिक सूचना दिनांक 21 मार्च 1989 द्वारा टीडीएम को सूची से हटाकर एलएमपोफ्ट और निर्यात नीति में संशोधन किया गया

ओजीएल द्वारा कवर की गई वस्तुओं की संख्या। इसलिए, 21 मार्च 1989 के बाद टीडी एमएस के आयात के लिए नियंत्रण आदेश के खंड 3 (1) के संदर्भ में लाइसेंस की आवश्यकता थी। हालाँकि, सार्वजनिक नोटिस ने बिना लाइसेंस के टीडीएम के कुछ आयात की अनुमति दी नोटिस के पैराग्राफ 4 में वर्णित शर्तों की पूर्ति के अधीन,

निम्नानुसार: ·

> "इस सार्वजनिक सूचना आयात के संदर्भ में ओपन जनरल लाइसेंस से बाहर किए गए कच्चे माल, घटकों और

उपभोग्य सामग्रियों के संबंध में पात्र आयातक द्वारा ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत नहीं किया जाएगा क्रेडिट के अपरिवर्तनीय पत्रों की सीमा को छोड़कर अनुमति दी गई है इस सार्वजनिक तिथि से पहले ही खोला और स्थापित किया जा चुका है सूचना जिसके लिए शिपमेंट नब्बे की अवधि के भीतर किए जाते हैं इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से (90) दिन।"

(18) उत्तरदाताओं ने इस छूट का लाभ उठाने की मांग की। इस कोने तक, 26 मई 1989 को, प्रतिवादी नंबर 1 ने रिज़र्व बैंक को लिखा भारत ने बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से कहा कि उसे मेसर्स द्वारा सूचित किया गया था मोहन एलएमपीईएक्स ने कहा कि सामग्री 'जुलाई से पहले शिपमेंट के लिए तैयार नहीं होगी 1989. चूँकि हमें सुनिश्चित करने के लिए टेप डेक तंत्र की तत्काल आवश्यकता है सुचारू उत्पादन के लिए हमने लाभार्थी को तत्काल व्यवस्था करने की सलाह दी शिपमेंट. तदनुसार, हमारा लाभार्थी एक जापानी आपूर्तिकर्ता को खरीद सकता है जो तत्काल डिलीवरी देने की स्थिति में है'. यह भी कहा गया कि आपूर्तिकर्ता, यमातो ने यह कहते हुए लिखा था कि वे 'माल

को रोके हुए हैं।' तैयार' और उस एल/सी में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए। का निहितार्थ यह पत्र यह है कि यमातो को उसी सामग्री की आपूर्ति करनी थी जिसके लिए ऑर्डर मेसर्स मोहन एलएमपीईएक्स को दिया गया था और वह यमातो था मैसर्स का एजेंट। मोहन एलएमपीईएक्स.

(19) संयोग से, प्रतिवादी नंबर एल के निदेशक ने बाद में स्वीकार किया कि एल/सी में संशोधन गलत तरीके से प्राप्त किया गया था-यह संदेश कि मिस ने यमातो को प्रतिवादी नंबर 1 से मिलवाया था मई 1995 में मोहन इम्पेक्स। वास्तव में, प्रतिवादी नंबर 1 और उसके निदेशक यमातो और उसके साझेदार कई वर्षों से व्यक्तिगत रूप से जाने जाते थे यमातो मैसर्स से पूर्णतः स्वतंत्र था। मोहन इम्पेक्स.

(19-ए) कलेक्टर ने माना कि बैंक ऑफ इंडिया की सहमति और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा साख पत्र में संशोधन मेसर्स के स्थान पर यमातो को प्रतिस्थापित करना। मोहन एलएमपीईएक्स और बंदरगाह में परिवर्तन टीडीएम की उत्पत्ति के स्थान पर शिपमेंट दमन द्वारा प्राप्त किया गया था और आवश्यक तथ्यों की गलत प्रस्तुति। यह भी माना गया कि का पत्र क्रेडिट जो मेसर्स के भुगतान के लिए संचालित किया गया था। यमातो वास्तव में नया था साख पत्र और इसलिए यमातो से टीडी एमएस का

आयात किया गया था 21 मार्च 1989 की सार्वजनिक सूचना के खंड 4 में शामिल नहीं है। ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रतिवादियों के वकील ने इसके लिए दबाव नहीं डाला जनवरी 1989 से साख पत्र की वैधता और माना कि यह हो सकता है यह माना जाएगा कि क्रेडिट पत्र मई 1989 में खोला गया था जैसा कि उसके पास था एकत्र करनेवाला।

(19-बी) इसे देखते हुए, टीडी एमएस की एंटिन: खेप की आवश्यकता है आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के खंड (2) के तहत आयात लाइसेंस, 1947 और आयात से पहले आयात नियंत्रण आदेश, 1955 का खंड 3

(20) मुद्दे से संबंधित तथ्यों के विवरण पर लौटना मूल्यांकन. सार्वजनिक सूचना जारी होने के बाद कथित तौर पर यह बात सामने आई है टीडीएम के घोषित मूल्य में एस$343.50 से एस$250.00 प्रति सेट तक की गिरावट। यमातो एक जापानी कंपनी है। फिर भी 17.5.1989 को यमातो पर ऐसा होने का आरोप है प्रतिवादी नंबर 1 को कीमत उद्धृत करते हुए एक नया प्रोफार्मा चालान दिया गया कीमत येन में बताने के बजाय प्रति सेट सिंगापुर डॉलर। जैसा कि कहा गया है कलेक्टर ने "आयात नीति में बदलाव के कारण आयातकों को यह सुनिश्चित करने में विशेष रुचि है कि इकाई मूल्य को कम किया जाए आयात की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।'

टीडी एमएस के मूल्य में यह नाटकीय "गिरावट" वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती है टीडीएम का मूल्य दस्तावेजी और दोनों साक्ष्यों से पता चलता है मौखिक।

(20-ए) शुरुआत में यह स्पष्ट है कि यदि शिपमेंट यमातो द्वारा किया गया था 5 जनवरी 1989 को दिए गए मनगढ़ंत आदेश के अनुसार, इसके द्वारा घोषित मूल्य को वास्तविक नहीं माना जा सकता। के कलेक्टर देखें सीमा शुल्क, कलकत्ता बनाम संजय चांदीराम, [1995) 4 एससीसी 222। इसलिए टीडीएम का मूल्य कानून के अनुसार निर्धारित करना होगा लागू.

(20-बी) अधिनियम की धारा 14(1) मूल्य के संदर्भ में मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्यांकन का प्रावधान करती है जिस पर "ऐसे या जैसे" सामान" आमतौर पर आयात के समय और स्थान पर बेचा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का.

(20-सी)कलेक्टर, ट्रिब्यूनल के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं के अधिकांश तर्क इस आधार पर आगे बढ़ते हैं जैसे कि यह था स्थापित किया गया कि टीडीएम जिनकी आपूर्ति मेसर्स द्वारा की जानी थी। मोहन एलएमपीईएक्स वास्तव में यमातो द्वारा आपूर्ति किए गए टीडीएम से भिन्न थे। यह तर्क दिया गया कि मैसर्स. मोहन इम्पेक्स को राष्ट्रीय टीडीएम की आपूर्ति करनी थी मॉडल जबकि मै. यमातो ने एनईसी मॉडल के वीसीऔर की आपूर्ति की थी। इसके लिये अंत में, एनईसी मॉडल

टीडीएम की कीमत के संबंध में कई दस्तावेज उत्तरदाताओं द्वारा उन पर भरोसा करने की भी मांग की गई। का आधार तर्क कभी स्थापित नहीं हुआ और साक्ष्य के विपरीत था।

(21) सबसे पहले, प्रतिवादी नंबर 1 ने साख पत्र का उपयोग किया मेसर्स मोहन इम्पेक्स से एस$260 प्रति सेट की दर से टीडीएम के 500 सेट आयात करें और यमातो से एस$250 पर टीडी एमएस के 30 सीओ सेट। मेसर्स मोहन से 500 सेट इम्पेक्स बंबई पहुंचा और यमातो से 3000 सेट कांडला पहुंचे। हालाँकि, वास्तव में साख पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था उस वस्तु की प्रकृति का सम्मान जिसके लिए शुरू में ऋण पत्र जारी किया गया था खोला गया, अर्थात्, "इलेक्ट्रॉनिक्स घटक, अर्थात्, टेप डेक तंत्र, आदेश क्रमांक टीसी-89-004 5:89" के अनुसार। दूसरे शब्दों में, प्रकार और टीडी एमएस की दर एस 343.45 समान रही। पत्र का लाभ उठाने में श्रेय की बात यह है कि संबंधित पक्षों ने इसे पूरा करने के लिए ऐसा किया है मोहन एलएमपीईएक्स पर दिए गए मूल ऑर्डर में जहां दर का उल्लेख किया गया है।

(22) दूसरे, यमातो का चालान जो सीमा शुल्क के साथ दायर किया गया था अधिकारियों ने टीडीएम को 'वीसीऔर के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक' के रूप में भी वर्णित किया है अर्थात. आदेश संख्या टीसी/89/004 दिनांक 5.1.89' के अनुसार टेप डेक तंत्र। जैसा पहले ही उल्लेख किया गया है, इसे

प्रतिवादी संख्या एल के निदेशक ने अपने में स्वीकार किया था धारा 108 के तहत बयान, कि वास्तव में कोई आदेश नहीं दिया गया था यमातो 5 जनवरी 1989 को और एकमात्र वास्तविक ऑर्डर वह था जो दिया गया था मैसर्स मोहन इम्पेक्स पर। चूंकि यमातो ने टीडीएम के 3000 सेट की आपूर्ति की है मोहन इम्पेक्स के आदेश के अनुसार, इसे आपूर्ति करना माना जाना चाहिए समान सामान की दर S343.45 प्रति सेट। ति सेट S143.45 था।

(23) तीसरा, कि टीडीएम जो यमातो द्वारा आपूर्ति किए गए थे वही जिनके लिए मेसर्स मोहन को ऑर्डर दिया गया था इम्पेक्स को धारा 108 के तहत दर्ज किए गए बयानों से भी समर्थन मिलता है अधिनियम का. (इस संबंध में देखें: नरेश जे. सुखवानी वीओ यूनियन ऑफ बीटीडिया, प्रतिवादी नंबर एल के निदेशक और सहायक प्रबंधक ने डीऔरआई के समक्ष धारा 108 के तहत अपने बयानों में इसकी पुष्टि की अधिनियम के अनुसार जो टीडीएम यमातो द्वारा भेजे गए थे वे वही थे जिनके लिए ऑर्डर मिस मोहन इम्पेक्स को दिए गए थे।

द असिस· प्रतिवादी नंबर 1 के टेंट मैनेजर ने कहा कि मैसर्स के साथ आदेश बी मोहन इम्पेक्स को बाद में यमातो को 'स्थानांतरित' कर दिया गया, न कि उन्हें नया ऑर्डर दिया गया. यहां तक कि प्रतिवादी नंबर 1 के प्रबंध निदेशक भी मुझे यह कहना था।

"मैं यह भी कहता हूं कि एमआईएस के साथ अनुबंध में जो भी आइटम दर्ज किया गया था एल/सी के लिए मोहन इम्पेक्स जनवरी '89 में उनके साथ खुला सी वही रहा (लेकिन नाम के लिए) - यहां तक कि हमारे नए अनुबंध में भी यमातो जापान. इस प्रकार, हमारे ताज़ा में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है मिस यमातो के साथ अनुबंध।"

(24) अब, यमातो द्वारा आपूर्ति किए गए टीडीएम पर कोई अंकन नहीं था और एमआईएस मोहन इम्पेक्स के आदेश में मॉडल का उल्लेख नहीं किया गया, दिलचस्प बात यह है कि धारा 108 के तहत अपने बयान में प्रतिवादी नंबर 1 के समाशोधन एजेंट

कहा:

"सामान्य अनुभव के आधार पर यह कहा गया है कि यह एक तथ्य है हालाँकि आयातक कांडला बंदरगाह पर सीमा शुल्क को बता रहा था कि ये टी.डी.एम. राष्ट्रीय 0-30 के नहीं हैं, हो भी नहीं सकते इनका प्रमाण है क्योंकि यह निर्विवाद है कि (टेप डेक) राष्ट्रीय जी-30 का तंत्र (मैकेनिज्म) 100% यूनिस के समान है अब आयातक द्वारा मंजूरी दे दी गई है। मैं सिर्फ अपने आधार पर ही कह सकता हूं इस आइटम को विशेष रूप से संभालने का अनुभव (वी.सी.और./टी.वी. और उनका)। घटक) कुछ

आयातकों और अन्य सहायक कंपनियों के लिए प्रति नमूना निकाला गया और डी.और.आई. को प्रस्तुत किया जा रहा है। आज, यह है राष्ट्रीय जी-30 के समान और समान लेकिन केवल जी-30 मार्किंग के लिए इन सेटों पर नहीं दिखाया जा रहा है. इस व्यापार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति जान सकता है जैसा कि यह अमुक निर्माता की व्यापारिक जानकारी है।"

(25) फिर से क्लियरिंग एजेंट ने कहा कि टीडीएम की कीमत इस प्रकार है प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिखाया गया असामान्य रूप से कम था। उसने कहा:

> "मुझे बहुत। अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली खेपों में भी ऐसा ही था S250 प्रति सेट पर इतना कम कभी नहीं। टेप डेक तंत्र कभी नहीं रहा किसी भी मॉडल के लिए किसी भी आयातक के लिए मेरे द्वारा पारित किया गया है। मैंने आयातक से कहा था कि यह मूल्य बहुत कम है लेकिन उन्होंने कहा कि वे ऐसा करेंगे यह दिखाकर प्रबंधन करें कि ये सामान अलग थे। पार्टी भी उन्होंने कहा कि वे यह दिखाने के लिए किसी इंजीनियर को तैयार करेंगे कि ये थे भिन्न जबकि मैंने अपने अनुभव के आधार पर उन्हें बताया कि ये जो सामान मैं साफ़ कर रहा था उससे अलग नहीं

दिख रहा था उनकी ओर से. लेकिन उन्होंने कहा कि वे किसी इंजीनियर को लाने की कोशिश करेंगे।"

(26) उत्तरदाताओं ने 10 तारीख के चालान पर भरोसा करने की मांग की एमएनऔरएच 1989 एनईसी द्वारा यमातो को पारित किया गया जिसके लिए कीमत दिखाई गई थी लगभग 237.00 एस प्रति सेट। चालान से आगे पता चला कि शिपमेंट भारत में किया जाना था। तारीख का महत्व नहीं था कलेक्टर पर गुस्सा आया जिसने नोट किया कि यह शिपमेंट से संबंधित नहीं हो सकता है प्रश्न यह है कि टीडीएम की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया था मई 1995 में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा यमातो। कलेक्टर ने टीडीएम के एनईसी मॉडल के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा उत्पादित दो अन्य चालानों के साक्ष्य मूल्य को भी इस आधार पर कम कर दिया कि वे संबंधित थे खेप के आयात की तारीख के बाद 8 से 10 महीने के आयात के लिए प्रश्न में।

(27) दूसरी ओर कलेक्टर ने पहले के चालानों पर भरोसा किया टीडीएम एस एस 343.45 प्रति सेट का मूल्य दिखा रहा है। रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है यह दिखाने के लिए कि पहले के चालान में आपूर्ति किए गए प्रकार के टीडी एमएस का उल्लेख नहीं था डब्ल्यूजेएस यमातो द्वारा। प्रतिवादी क्रमांक 1 के सहायक प्रबंधक ने बुरा स्वीकार किया प्रतिवादी नंबर

1 ने एक ही टीडीएम (4) के कई शिपमेंट को प्रभावित किया था 5 शिपमेंट तक) पहले।

(28) कलेक्टर ने वर्णित परिस्थितियों में, यमातो द्वारा आपूर्ति किए गए टीडीएम के मूल्य को "ऐसे या जैसे" के रूप में सही ढंग से निर्धारित किया माल जिसके लिए ऑर्डर मिस मोहन एलएमपीईएक्स पर दिया गया था अधिनियम की धारा 14(1) का अर्थ.

(29) कलेक्टर का निष्कर्ष भी धारा 14 के अंतर्गत न्यायोचित है (एलए) अधिनियम के. धारा 14(1ए) कीमत के निर्धारण का प्रावधान करती है के प्रावधानों के अधीन इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार उपधारा (1). इस संबंध में जो नियम बनाए गए हैं सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम 1988 (इसके बाद मूल्यांकन नियम के रूप में संदर्भित)।

(30) मूल्यांकन नियमों के नियम 3 में निर्धारण का प्रावधान है मूल्यांकन की विधि और कहा गया है कि:

"इन नियमों के प्रयोजन के लिए:- (i) आयातित वस्तुओं का मूल्य लेनदेन मूल्य होगा;

(ii) यदि के प्रावधानों के तहत मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है उपर्युक्त खण्ड (i) के अनुसार मूल्य कार्यवाही द्वारा निर्धारित किया जाएगा इन नियमों के नियम 5 से 8 के माध्यम से क्रमिक रूप से।"

(31) नियम 4 उपनियम (2) में प्रावधान है कि आयातित माल का लेनदेन मूल्य स्वीकार किया जाएगा। लेनदेन मूल्य को रुइक 4 के उप-नियम (1) में माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के रूप में परिभाषित किया गया है। जब हम कुछ समायोजनों के अधीन भारत में निर्यात के लिए बेचे जाते हैं चिंतित नहीं हैं।

(32) यमातो ने आदेश संख्या टीसी/89/004 दिनांक के अनुसार टीडीएम की आपूर्ति की 5.1.89 जिसकी आपूर्ति के लिए मेसर्स मोहन एलएमपीएक्सएक्स को ऑर्डर दिया गया था टीडीएम एस 343.45 प्रति सेट पर। "उस सामान के लिए देय कीमत बनी रही एस 343.45 प्रति सेट। इस मामले में आयात के समय भी लेनदेन मेसर्स मोहन एलएमपीएक्सएक्स पर दिए गए ऑर्डर का हवाला दिया गया। में देय मूल्य टीडीएम के लिए उस लेनदेन का मूल्य एस 343.45 प्रति सेट था। यह हो सकता है, इसलिए, बता दें कि लेनदेन मूल्य एस 343.45 प्रति टीडी एम सेट था नियम 3 के अर्थ में।

(33) न्यायाधिकरण के दो सदस्यों की निंदा जिन्होंने अलग कर दिया कलेक्टर का आदेश इस भ्रामक आधार पर आगे बढ़ाया गया कि

कलेक्टर दो अलग-अलग तारीखें नहीं अपना सका, एक एल/सी की तारीख से और अन्य मूल्यांकन की तारीख से। उन्होंने चालान पर भी भरोसा किया एनईसी द्वारा दिनांक 10 मार्च जे989 जारी किया गया और साथ ही इसका एक बयान भी जारी किया गया। एकत्र करनेवाला इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संदर्भ से बाहर उद्धृत किया गया कि यह स्पष्ट था टीडी एमएस का मूल्य काफी हद तक गिर गया था।

(34) दोनों सदस्यों ने कलेक्टर के आदेश को पूरी तरह से गलत पढ़ा। कलेक्टर ने एल/सी की तारीख का उल्लेख केवल सार्वजनिक सूचना के पैराग्राफ 4 की प्रयोज्यता के संबंध में किया था, मूल्यांकन के संबंध में बिल्कुल नहीं। उन्होंने कलेक्टर के बयान को भी गलत बताया कीमतों में गिरावट के संबंध में. उन्होंने जो कहा था वह यह था कि कीमत में गिरावट आई है इम्पोन नीति में बदलाव के कारण टीडीएम में हेरफेर किया गया था जिसमें टीडी एमएस के आयात को काफी हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया था।

(35) इसलिए, हम कलेक्टर के निष्कर्ष को बरकरार रखेंगे टीडीएम की इकाई कीमत एस 343.45 और साथ ही उसका ऑर्डर भी विभेदक शुल्क के भुगतान के संबंध में।

(36) अपीलकर्ता द्वारा हमारे सामने उठाया गया दूसरा मुद्दा यह है कि क्या के आयात को कवर करने वाले लाइसेंस की स्वीकार्यता का प्रश्न

टीडीएम को ट्रिब्यूनल द्वारा रिमांड पर लिया जाना चाहिए था। लो के अनुसार अपीलकर्ता, टीडीएमओ का आयात स्पष्ट रूप से आयात और निर्यात का उल्लंघन करता है (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात नियंत्रण अध्यादेश 1955। यह प्रस्तुत किया गया है टीडीएम का आयात वहां बिना लाइसेंस के किया गया था आयात के बाद लाइसेंस जमा करने का कोई सवाल ही नहीं है। अनुसार उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता को मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि अपीलकर्ता ने पहले की कार्यवाही में भाग लिया था रिमांड के बाद कमिश्नर ने कहा कि सुनवाई आगे बढ़ रही है।

(37) हम उत्तरदाताओं की अधीनता स्वीकार करते हैं, जमीनी स्तर पर नहीं आगे रखा गया लेकिन क्योंकि ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीलकर्ता का प्रतिनिधि था ने स्वीकार किया था कि इस मुद्दे का निर्णय मूल प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए उच्च न्यायालय के आदेश की शर्तें। फिर भी, हम स्पष्ट करना चाहेंगे निर्णय प्राधिकारी के समक्ष मुद्दे का दायरा।

(38) यह स्पष्ट नहीं है कि हाई कोर्ट को किस आधार पर राजी किया गया आयात के बाद आयात लाइसेंस प्रस्तुत करने की अनुमति दें माल। हालाँकि, मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया कानून के अनुसार, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय नहीं लिया क्या प्रतिवादी संख्या एल द्वारा लाइसेंस पर बिल्कुल भी भरोसा किया जा सकता है

नियंत्रण के खंड (3) के उल्लंघन के लिए अपने दायित्व से बचने के लिए आदेश देना। इसलिए, निर्णायक प्राधिकारी को निर्णय लेना होगा (i) क्या कानून में, पहले से ही वस्तुओं के संबंध में एक लाइसेंस बाद में तैयार किया गया है आयातित कानून में स्वीकार्य है, (ii) यदि हां, तो क्या वास्तव में लाइसेंस कवर किया गया है आयातित वस्तुएँ अन्यथा वैध हैं।

(39) यह हमें दंड के प्रश्न पर लाता है। इसे याद रखना है कि कलेक्टर ने 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रतिवादी पर 40 लाख रु नंबर 1 टीडी एमएस के मोचन मूल्य के बराबर है जो थे जब्ती के लिए उपलब्ध नहीं है और रु. प्रतिवादी क्रमांक पर प्रत्येक पर 5 लाख रु. एल के निदेशक. यह जुर्माना इस अर्थ में संयुक्त था आयात नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के कारण दोनों लगाए गए मूल्य की गलत घोषणा और सीमा शुल्क की चोरी के कारण। बहुमत ने प्रतिवादी नंबर 1 पर जुर्माना रद्द कर दिया क्योंकि वे कम मूल्यांकन और कर चोरी के निष्कर्ष को भी नकार दिया रिमांड का आदेश. पाए गए उल्लंघनों के बीच जुर्माने की मात्रा का बंटवारा करना संभव नहीं है। इसलिए, यद्यपि हमने इसे कायम रखा है गलत घोषणा और कर चोरी के मुद्दे पर कलेक्टर के निष्कर्ष पर सवाल जुर्माने की राशि कलेक्टर द्वारा पुनः निर्धारित की जायेगी लाइसेंसिंग पहलू पर मुद्दे का निर्धारण।

(40) हम यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला गया कि लगाया गया जुर्माना अनुचित था। दूसरी ओर, असहमति रखने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमांड के खिलाफ राय दी थी, उसने हमारी राय में सही माना था कि मामले की परिस्थितियों में जुर्माने की राशि उचित थी।

(41) तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जहां तक यह गलत घोषणा के निष्कर्ष से संबंधित है, ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द कर दिया गया है और टालमटोल. अंतर भुगतान हेतु कलेक्टर का आदेश कर्तव्य की पुष्टि की गई है. आयात नियंत्रण के उल्लंघन के प्रश्न पर आदेश, निर्णय प्राधिकारी के आलोक में मामले का निर्णय करेगा प्रश्न पहले तैयार किए गए। उसके निर्णय के आधार पर जुर्माने की मात्रा इस निर्णय के निष्कर्ष के आलोक में कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जाएगी। उत्तरदाता अपीलकर्ता को अपील की लागत का भुगतान करेंगे, जिसका मूल्य रु. 5000।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद और्टिफिशयल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पृथा फौजदार (और.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद`देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद`देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद`देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।